भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 755

05.02.2021 को उत्तर के लिए

वन संसाधनों में बढ़ोत्तरी हेतु योजनाएं

755 सुश्री सुनीता दुग्गल :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वन संसाधनों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा हरियाणा को उक्त योजना के अंतर्गत कितनी निधि प्रदान की गई है;

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान भारत की वन रिपोर्ट (आईएसएफआर) के अनुसार देश में वनरोपण की स्थिति क्या है;

(घ) क्या राज्य में वन संसाधनों को बढ़ाने के लिए हरियाणा राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा देश में वन संसाधनों में वृद्धि करने हेतु दो प्रमुख वनीकरण योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं, नामत: अवक्रमित वनों में लोगों की भागीदारी के माध्यम से वृक्षारोपण हेतु राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) और भू-परिदृश्य के आधार पर पौधरोपण के लिए राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम)।

इसके अलावा, प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (काम्पा) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वनीकरण कार्यकलापों को संचालित करने हेतु निधियां जारी की जाती हैं, जिसके माध्यम से भी हरित आवरण में वृद्धि होती है।

(ख) वर्ष 2019 के दौरान, हरियाणा राज्य के राज्य काम्पा को प्रतिपूरक वनीकरण शुरू करने हेतु काम्पा के राष्ट्रीय प्राधिकरण से 1282.65 करोड़ रूपए की धनराशि अंतरित की गई है। तथापि, गत दो वर्षों के दौरान हरियाणा राज्य को एनएपी तथा जीआईएम के तहत कोई निधियां प्रदान नहीं की गई हैं।

(ग) नवीनतम 'भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर-2019) से स्पष्ट हुआ कि आईएसएफआर-2017 में आकलित 802,088 वर्ग किमी (देश के भौगोलिक क्षेत्रफल के 24.39 प्रतिशत) की तुलना में देश का कुल वनावरण और वृक्षावरण 807.276 वर्ग किलोमीटर है (जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56 प्रतिशत है)। पूर्व के आकलन अर्थात् आईएसएफआर-2017 की तुलना में, राष्ट्रीय स्तर पर, वन और वृक्षावरण को मिलाकर 5,188 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है।

(घ) और (ड.) काम्पा वार्षिक प्रचालन योजना के तहत, वनीकरण सहित विभिन्न कार्यकलापों को शुरू करने हेतु वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए क्रमश: 96.84 करोड़ रूपए और 181.29 करोड़ रूपए की मंजूरी प्रदान की गई। गत दो वर्षों के दौरान, हरियाणा राज्य से राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के तहत वनीकरण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और हरित भारत मिशन के तहत हरियाणा राज्य ने भू-परिदृश्य आधारित वनीकरण के लिए अपनी परिदृश्य योजना प्रस्तुत की है।

*****